रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1751] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2019/ज्येष्ठ 23, 1941
No. 1751] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2019/JYAISTHA 23, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2019

का.आ. 1959(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि रक्षा प्रतिष्ठान में उद्योगों से लगी सेवाएं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 8 के अंतर्गत आती हैं उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी लोक उपयोगी सेवा होगी।

और केन्द्रीय सरकार अंत में यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी लोक उपयोगी सेवा होगी, जिसे इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 6210(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2018 द्वारा 22 दिसम्बर, 2018 से छह मास की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त अवधि का छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा प्रतिष्ठानों से लगी सेवाओं को 22 जून, 2019 से छह मास की और अवधि के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/97-आई.आर.(पी.एल.)]
कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2019

S.O. 1959(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the industry of Defence establishments, which is covered under item 8 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 22nd December, 2018 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 6210(E), dated the 18th December, 2018;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in Defence Establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 22nd June, 2019**.**

[F.No. S-11017/5/97-IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT**,** Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.06.14 10:57:37 +05'30'